

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास विभाग,  
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग:

देहरादून: दिनांक-06 मार्च, 2006

विषय : नगर पालिका परिषद, मसूरी, जनपद देहरादून में अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न कार्यों की वित्तीय वर्ष-2005-06 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद, मसूरी, जनपद देहरादून में प्रस्तावित कार्यों हेतु प्रस्तुत रु०-789.57 लाख की लागत के आगणन विपरीत टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु०-707.72 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० 141.52 (रुपये एक करोड़ इकतालिस लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2- अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा, किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाय, इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 3- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समगबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
- 6- कार्य करने के पूर्व यह सुनिश्चित करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा कि उक्त कार्य मा० उच्चतम न्यायालय के स्टे के निर्णय से बाधित न हो। यदि स्टे से निर्माण कार्य

प्राप्ति

(समाप्ति)

आच्छादित हो तो स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

- 7- उक्त अनुदान आवर्तक नहीं है और भविष्य में उक्त मार्गों के अनुक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त मार्ग नगर पालिका परिषद के ही क्षेत्राधिकार में हों और अन्यथा कि स्थिति में स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके धनराशि शासन को अविलम्ब समर्पित कर दी जायेगी।
- 8- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुरितका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज कल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- 9- निर्माण एजेंसी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 10- यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को एक माह के भीतर समर्पित कर दी जायेगी।
- 11- कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात् योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के स्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा। कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व व पूर्ण करने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ई0ओ0 के माध्यम से निदेशक को कार्य के चित्र लेकर प्रेषित किया जायेगा।
- 12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किशतों में आहरण किया जायेगा।
- 13- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किशतों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किशत तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
- 14- आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 15- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- 16- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

राम  
(नगरपालिका प्रमुख)  
नगर प्रमुख  
नगर प्रमुख  
नगर प्रमुख



- 17- विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
- 18- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- 19- शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को एक वर्ष के भीतर उपलब्ध करा दिया जाये। और उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।
- 20- कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- 21- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2005-06 के आय-व्यय के अनुदान सं0-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 22- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 331/XXVII(2)/2006, दिनांक- 04 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)  
सचिव।

सं0 479(1) / V-श0वि0-06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
- 6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
- 7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड बुक।

नाम

आज्ञा से,  
( एल0 फैनई )  
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 479 / व-श0वि0-06-271(सा0) / 05

दिनांक ०6 मार्च, 2006 का संलग्नक ।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	आगमन की लागत	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित आगमन	अवमुक्त की जा रही धनराशि
01	लाइब्रेरी गांधी चौक के निकट गाडीखाना में कार पार्किंग व स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	156.70	113.21	22.64
02	नगरपालिका परिषद मसुरी के अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में नालों का विकास व निर्माण कार्य	126.10	119.10	23.82
03	पालिका सीमान्तर्गत विभिन्न वार्डों में मार्गों का विकास व निर्माण कार्य	383.50	356.30	71.26
04	वार्ड न०-1 में घर सड़कों का निर्माण / सुधार कार्य	53.57	53.45	10.69
05	वार्ड न०-2 में विभिन्न कार्य	69.70	65.56	13.11
	कुल योग-	789.57	707.62	141.52

(रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख बावन हजार मात्र)

नाम

(साक्षी - अध्यक्ष)

नाम  
पद